MEHTA): (a) and (b). No Sir. Except for a few categories of Class III services for which recruitment is made on an All-India regional basis, recruitment for vacancies in Class III and Class IV services is generally made by drawing candidates who have registered themselves in the Employment Exchanges serving the areas in which the Central Government offices are situated.

Increase in Pension of Service Personnel

*233. SHRI N. K. SANGHI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to increase the amount of pension nearly by 50 per cent in case of the army service personnel; and

(b) if so, whether same rates of enhanced pension will be made applicable to other service personnel from Navy and Air Force?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI BANSI LAL): (a) The actual extent of increase of pension, as also the percentages by which pension has been increased, are indicated in the statement laid on the Table of the House.

(b) The rates of service pension of corresponding ranks in the Navy and the Air Force have also been raised

Statement

Statement showing the improvement in the rates of retiring Pension of Armed Forces Personnel

Personnel below officer rank

Rank	Old rates of pension		New rates of pension		Increase in percentage	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
	Rs. p.m	Rs. p.m.	Rs. p m	Rs. p m	Rs. p.m	Rs. p m.
Sepoy . . .	40 00	72·00	76 00	122 00	90%	69 44%
Naik	40·00	81 00	86 00	135·00	155%	66·67%
Havildar . . .	43 00	91 00	98 00	159 00	127·9%	74·73%
Nb. Subedar . . .	60·00	122·00	127 00	223 00	111 66%	82·79%
Subedar . . .	80·00	178 00	162·00	308·00	102·5%	73·03%
Subedar-Maj. . .	106·00	218·00	197·00	366·00	85·8%	67·89%

Permanent Commissioned Officers

Rank	Old rates of pension	New rates of pension	Increase in Percentage
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
Subaltern	272·00	350·00	28·68%
Captain	377·00	575·00	32·52%
Major	482·00	675 00	40·04%
Lt. Colonel	587·00	775 00	32·03%
Colonel	638·00	900·00	41·07%
Brigadier	696·00	1000·00	43·68%
Major General	735 00	1050 00	42·86%
Lt. General	819·00	1100 00	34·31%
General (Chief of the Army Staff)	1008·00	1200·00	39·05%

राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये लम्बित राज्यों के विधेयक

*235. **श्री रामावतार शास्त्री** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य विधान-सभाओं द्वारा पारित बहुत से विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये महीनो से लम्बित पड़े है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विधेयको का राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने मे विलम्ब होने के क्या कारण है ?

गृह मंत्री श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : (क) से (ग) : स्वीकृति के लिये प्राप्त विधेयकों का निपटान सामान्यतया परम अग्रता के आधार पर किया जा रहा है। महत्वपूर्ण नीति विवादों के मामलो मे सबंधित मंत्रालय वास्तव मे अपना अन्तिम मत देने से पहले पेचीदगियो की जांच करने के लिये समय लेते हैं। कुछ मामलो मे राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण प्राप्त करना पड़ता है जिसमे लम्बा पत्र व्यवहार करना होता है। केवल ऐसे ही मामलों मे राष्ट्रपति की स्वीकृति मे विलम्ब होता है।

ऐसे मामलों के राज्यवार ब्यौरे जो दो मास से अधिक पुराने हैं, नीचे दिये गये हैं:—

असम . .	2
बिहार . .	1
हरियाणा . .	3
केरल . .	3
मध्य प्रदेश . .	2
मणिपुर .	2
उड़ीसा . .	1
पजाब . . .	1
राजस्थान . . .	1
तमिलनाडु . .	5
उत्तर प्रदेश . .	1
पश्चिम बंगाल . .	1